International Journal of Hindi Research
ISSN: 2455-2232; Impact Factor: RJIF 5.22
Received: 20-10-2020; Accepted: 05-11-2020; Published: 23-11-2020
www.hindijournal.com
Volume 6; Issue 6; 2020; Page No. 70-73

21वीं सदी की उच्च शिक्षा में तकनीकी पहल

ऋषिकेश सिंह

हिंदी विभाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली, भारत

सारांश

अपने पूर्ववर्ती सदियों से अधिक विकसित एवं अत्याधुनिक होती है। इसका प्रमुख कारण निरंतर होने वाले शोध से विकसित नए उपकरण, सुविधाएं, तकनीक आदि हैं। जो तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं शैक्षिक आदि क्षेत्रों में परिवर्तन हेतु प्रेरित करते हैं। शायद इसी कारण डॉ. अमरनाथ ने सटीक टिप्पणी की है; "आधुनिकतावादियों की नवीन से नवीनतर सृजन करने की तीव्र इच्छा के कारण प्रयोग अपने आप में भी और मूल्य बन जाता है। प्रतिक्षण नया होने कुछ अपूर्व विलक्षण या अद्‌वितीय प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।" (पृष्ठ- 61, हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली) उदाहरण के तौर पर 18वीं सदी जहां औद्‌योगिक क्रांति, 19वीं-20वीं सदी संचार क्रांति वहीं 21वीं सदी भूमंडलीकरण जैसी बड़ी परिघटना के साथ-साथ सूचना प्रौद्‌योगिकी के तौर पर तकनीकी क्रांति तुल्य परिवर्तनकारी उपादानों का युग है।

मूल शब्द: अत्याधुनिक, उपकरण, राजनीतिक, सांस्कृतिक

प्रस्तावना

ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अनुसार हाइपरसोनिक्स, 5-जी इंटरनेट, जेनेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थ्री-डी प्रिंटिंग संबंधित तकनीक से तय होगा कि विश्व पर किस का दबदबा होगा। वर्षों पूर्व भारत के दूरदर्शी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस संदर्भ में अपनी भविष्य की चिंता को निम्न शब्दों में जाहिर किया था; "21वीं सदी हमें दस्तक दे रही है। यह सूचना की तकनीक की सदी होगी। भारत की सबसे बड़ी शक्ति बुद्‌धिमत्ता है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षित व्यक्ति की दृष्टि से विश्व में हमारा तीसरा स्थान है। हमें इस शक्ति का दोहन करना होगा।" (पृष्ठ-125, अटल उद्‌गार, संपादक- राकेश गुप्ता) इस प्रकार 21वीं सदी में तकनीकी महनीयता को समझा जा सकता है।

जहां तक बात शिक्षा क्षेत्र विशेषतः उच्च शिक्षा की है तो विकसित एवं विकासशील दोनों प्रकार के देशों में इस संबंध में एक व्यापक अंतर दिखाई देता है। विकसित देश जहां एक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी जी.डी.पी. का एक समुचित हिस्सा खर्च कर उसे नवाचार का केंद्र बना पुनश्च अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं, वहीं विकासशील देशों में इस क्षेत्र को लेकर एक पारम्परिक विचार कार्य करता है कि शिक्षा क्षेत्र द्रुत स्तर पर उत्पादक नहीं होता। अतः इस पर अधिक खर्च मौद्रिक व्यवस्था पर अधिभार है। जबकि इसके उलट कई समितियां व आयोग खर्च के स्तर को लगातार बढ़ाने की मांग कर रहे होते हैं, ताकि शोध और नवाचार के क्षेत्रों को व्यापक किया जाए। इस प्रकार तथ्यगत स्तर पर एक स्थापना स्थापित की जाती रही है कि विकासशील देशों में शिक्षा क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन प्रायः द्रुतगामी नहीं होते। किंतु आपद काल में व्यवस्थाएं वैकल्पिक समाधान की ओर तत्क्षण

शिफ्ट हो जाती हैं। शायद इसी कारण वर्तमान दौर में जब संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी के स्वास्थ्य आपातकाल से पीड़ित है एवं मनुष्य स्वस्तित्व हेतु संघर्ष कर रहा है, ऐसे में सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों के कई क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन हो रहे हैं। सरकारें लगातार नए साधनों एवं विकल्पों के प्रयोग पर जोर दे रही हैं। कहने का स्पष्ट आशय यह है कि डब्ल्यूएचओ द्वारा घोषित कोरोना महामारी के दूसरे क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव धीरे-धीरे सामने आएंगे लेकिन शिक्षा क्षेत्र में इसका असर अभी से दिखने लगा है। इस वायरस ने जिस व्यवस्था को सर्वाधिक प्रभावित किया है वह शिक्षा व्यवस्था एवं पठन-पाठन का क्षेत्र है। स्कूल से लेकर विश्वविद्यालयस्तरीय शैक्षणिक गतिविधियां लगभग ठप हो गई हैं। इस संबंध में माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री के इस आशावादी कथन को देखा जा सकता है कि; "इसके दृष्टिगत इस बड़े संकट से उबरने के लिए भारत के लगभग 1000 विश्वविद्यालय और 45 हजार से अधिक महाविद्यालय, 16 लाख से अधिक स्कूलों, एक करोड़ से अधिक अध्यापकों तथा 34 करोड़ विद्यार्थियों के नेटवर्क का बेहतर उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं।" (पृष्ठ-10, दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण) इस संदर्भ में जहां एक और अकारण उत्पन्न शैक्षणिक संकट से प्रभावित अध्यापक एवं विद्यार्थियों की चिंतायोग्य जानकारी है, वहीं दूसरी ओर इतने ही लोगों के सम्मिलित प्रयास एवं अन्य उपायों के लगातार तलाश से नए समाधान की आशावादी शोच भी है। हालांकि शैक्षणिक सत्र में होने वाले नुकसान को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने 'भारत पढ़े ऑनलाइन योजना' पर काम शुरू करके नई तकनीकी विकल्पों की खोज पर युद्ध स्तर की तैयारी आरंभ कर दी है। दूसरी ओर कुछ स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थान वैकल्पिक मॉडल के तौर पर अध्ययन-अध्यापन के डिजिटली स्वरूप के अंतर्गत आभासी कक्षा के रूप में माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, वेबेक्स सिस्को, गूगल मीट, यू ट्यूब ऑनलाइन, टीसीएस ऑयन डिजिटल क्लासरूम आदि पेड एवं प्रोफेशनल प्लेटफार्म का प्रयोग कर रहे हैं। जिससे शिक्षा जगत में एक नई तकनीकी पहल का आगाज हो रहा है।

हर-एक नई व्यवस्था, तंत्र एवं अवधारणा की तरह इस पहल के भी कई दूरगामी लाभ एवं तत्कालीन समस्याएं उभर कर सामने आ रहे हैं। जिसकी चर्चा भी इस संदर्भ में अत्यावश्यक है।

सर्वप्रथम बात यदि समकालीन चुनौतियों कि की जाय तो ये चुनौतियां मुख्यतः चार स्तर की हैं; 1- अनुप्रयोग संबंधी 2- आधारभूत ढांचा संबंधी 3- मूल्यांकन संबंधी 4- व्यवहारिक मूल्य संबंधी।

अनुप्रयोग संबंधी चुनौती से तात्पर्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के प्रयोग करने में आने संबंधी दिक्कतों से है। इसका संबंध तकनीक संबंधी जागरूकता या शिक्षा के अभाव से भी है। ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों या ऐसे छात्र-छात्राएं जिन्हें इन प्लेटफार्म के प्रयोग संबंधी बटन आईकॉन या अन्य एप संबंधी सामान्य जानकारियां नहीं है उन्हें प्रारंभिक स्तर पर इनका उपयोग कठिन जान पड़ेगा।

आधारभूत ढांचा संबंधी चुनौती इसकी मुख्य चुनौतियों में से एक है क्योंकि इसके अभाव में ही इन प्लेटफार्म की पहुंच आम छात्रों तक होने में कई तरीके की समस्याएं सामने आएंगी। इस चुनौती के कई रूप हैं, यथा इंटरनेट की अनुपलब्धता या स्पीड की समस्या, कनेक्टिविटी की समस्या, स्पष्ट ऑडियो-वीडियो के लगातार बने रहने की चुनौती, रिकॉर्ड करने की समस्या, डिजिटल कॉपी तैयार करना, प्रयोगात्मक परीक्षण की समस्या, शिक्षक-छात्र संवाद की चुनौती एवं इसके साथ-साथ प्रत्यक्ष उपस्थित ना हो पाने पर अनुप्रयोग संबंधी समस्या को दूर करने के लिए

केवल ऑनलाइन ट्यूटोरियल के माध्यम से ही जुड़ पाने एवं समस्या समाधान की असमर्थता, असमय तकनीकी के फेल हो जाने की समस्या आदि।

जिस तरह छात्रों के संबंध में जुड़ने, संवाद, नोट्स तैयार करना आदि डिजिटल समस्याएं हैं, वैसे ही शिक्षक पक्ष से एक बड़ी समस्या मूल्यांकन की भी है। जहां अभी तक मूल्यांकन की पारंपरिक प्रणाली के अंतर्गत एग्जाम कॉपी को भौतिक रूप से जांच कर मार्क्स या ग्रेड देने की परंपरा थी। वहीं ऑनलाइन स्तर पर कोई नई प्रणाली अभी तक विकसित ना हो पाने के कारण वर्चुअल प्लेटफार्म से तत्कालीन शिक्षकों की कम सहजता भी इस हेतु बड़ी बाधा है, साथ ही साथ एम.फिल., पीएच.डी., के स्तर पर प्री-सबमिशन, इंटरव्यू, थीसिस मूल्यांकन एवं उसके जमा कराने संबंधी कई व्यावहारिक समस्याएं भी मूल्यांकन के स्तर पर सामने आ रही हैं।

वर्चुअल प्लेटफार्म में जिस महत्वपूर्ण समस्या को शैक्षणिक विद्वानों द्वारा लगातार महसूस किया जाता रहा है एवं उसकी चर्चा की जाती रही है, वह है शैक्षिक व्यवहारिक मूल्य की समस्या। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा का तीन प्रमुख उद्देश्य माने जाते हैं- व्यक्ति एवं चरित्र निर्माण, लोक कल्याण, ज्ञान परंपरा का विकास। ऑनलाइन शिक्षा में इन लक्ष्यों की पूर्ति पर प्रश्नचिन्ह है। परंपरागत कक्षीय पठन-पाठन की प्रणाली में जहां ज्ञानदान के साथ-साथ अप्रत्यक्ष रूप से चरित्र निर्माण की सतत प्रक्रिया चलती रहती है। वहीं छात्रों में व्यापक साझेदारी, सामूहिकता, सहिष्णुता जैसे गुण भी विकसित होते रहते हैं। इसके साथ ही शिक्षक के क्रियाकलाप, व्यवहार व आचरण का छात्रों पर गहन प्रभाव पड़ता है। उसका चहुँमुखी विकास शैक्षिक परिसर में ही संभव है। वहीं शिक्षणेतर गतिविधियां अन्य प्रकार से उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती हैं। इस रूप में डिजिटली माध्यम शैक्षणिक क्षेत्र हेतु साधक नहीं बाधक के रूप में भी देखा जा रहा है।

कई स्तर की चुनौतियों के बाद भी इस नवाचारी माध्यम के वैकल्पिक समाधान एवं इसके दूरगामी हितों से दृष्टि फेरी नहीं जा सकती है। इसे इस रूप में भी देखा जा सकता है कि जहां एक और गुणवत्तापरक शिक्षा की सर्वग्रहयता एवं सर्वजनसुलभता में तीव्रतम वृद्धि होगी, वहीं दूरस्थ स्तरीय केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षकों से ग्रामीण क्षेत्रों का छात्र भी शिक्षा ग्रहण कर संवाद भी स्थापित कर सकता है। जिससे शिक्षा क्षेत्र संबंधी क्षेत्रीय असमानता को भी समाप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव इसका यह है कि प्रतिवर्ष उच्च शिक्षा हेतु भारत से बाहर जाने वाले छात्रों द्वारा बड़ी मात्रा में ले जाने वाले विदेशी मुद्रा पर भी अंकुश लगेगा क्योंकि अमेरिका एवं यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था में उच्च शिक्षा महत्वपूर्ण सहयोग करती है। एक एजेंसी के अनुसार इंग्लैंड की जी.डी.पी. का 1.2 फीसद योगदान विश्वविद्यालय करते हैं। जो इन्हें फीस एवं अनुदान से प्राप्त होती है। किंतु कोरोना वायरस के इस संकटकालीन दौर एवं नए माध्यमों की खोज में लगे विश्वविद्यालय, आई.आई.टी. एवं आई.आई.एम. जैसे लब्धप्रतिष्ठित संस्थान ऑनलाइन शिक्षण को क्लासरूम प्रोग्राम, वर्चुअल शिक्षण ऑन कैंपस के रूप में विकसित करने में लगे हुए हैं। उनके इस प्रयास में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जैसी महत्वपूर्ण संस्थाएं भी अपना पूरा सहयोग दे रही हैं। ऐसे में न केवल विदेशी शिक्षा के प्रति एक मजबूत विकल्प तैयार होगा बल्कि प्रधानमंत्री जी के तत्कालीन आह्वान के मूल मंत्र 'आत्मनिर्भरता' की दिशा में भी शिक्षा जगत का यह बड़ा कदम

होगा।

इस प्रकार सभी पक्ष-विपक्ष एवं तत्कालीन समय की आवश्यकता को ध्यान में रखकर कुछ पक्षों पर विचार किया जा सकता है। यथा; संभावित बाधाओं से संबंधित समाधान को प्रस्तुत करने, प्रणाली को रोजगारोन्मुखी बनाने, छात्र एवं शिक्षक के अनुकूल प्रणाली को विकसित करने आदि की महती आवश्यकता है, ताकि आने वाले समय में हम न केवल वर्तमान आपद काल जैसे संकट हेतु वैकल्पिक रूप से तैयार रहें, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक जगत में होने वाले परिवर्तन एवं नवाचारों सम्बन्धी अग्रणी देशों में हमारी उपस्थिति भी रहे।

संदर्भ विवरण

1. डॉ. अमरनाथ, हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली, पृष्ठ- 61
2. राकेश गुप्ता, अटल उद्‌गार, पृष्ठ-125
3. डॉ. रमेश पोखरियाल निःशंक, दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, पृष्ठ-10